

गाजा में हमास द्वारा गद्दारों की फांसी

गाजा में हाल के घटनाक्रम - हमास द्वारा सहयोगियों की फांसी - ने वैश्विक मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर तीखी बहस को फिर से भड़का दिया है। इन कृत्यों के बाद, एक परिचित पैटर्न उभरा है: हसबारा कथाओं के साथ जुड़े टिप्पणीकार जल्दी से फिलिस्तीनियों को “असभ्य” के रूप में निंदा करते हैं, और फिलिस्तीनी समर्थकों पर नैतिक आक्रोश व्यक्त करते हैं कि वे ऐसी फांसी की उतनी ही तीव्रता से निंदा नहीं करते। ये आरोप नए नहीं हैं - ये फिलिस्तीनी प्रतिरोध को अवैध ठहराने और गाजा तथा व्यापक फिलिस्तीनी आबादी पर थोपी गई असमान्य हिंसा और व्यवस्थित उत्पीड़न से ध्यान हटाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।

देशद्रोह का एक संक्षिप्त इतिहास

इतिहास में हर युद्ध में, राज्यों ने सहयोगियों को भर्ती करने की कोशिश की है - ऐसे व्यक्ति जो पैसे, सत्ता, या जीवित रहने के बदले में अपने ही पक्ष को धोखा देने को तैयार हों। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांसीसी प्रतिरोध और नाज़ी मुखबिरो से लेकर, इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियानों तक, और फिर इजरायल के फिलिस्तीन पर कब्जे तक, तर्क वही रहता है: खुफिया जानकारी एक शक्तिशाली हथियार है, और देशद्रोह उसकी कीमत है। गाजा कोई अपवाद नहीं है। फिर भी, इस संदर्भ में तथाकथित “गद्दारों” के प्रति प्रतिक्रियाएं एक विशेष रूप से विषाक्त और पाखंडी दृष्टिकोण से छनकर आती हैं।

गद्दारों का उल्लेखनीय चयन

“बंधकों को घर लाने” और “गाजा को भुखमरी से बचाने” के बारे में अनगिनत सार्वजनिक संदेशों के बाद, कोई यह उम्मीद कर सकता था कि इजरायल ने **बंधक मुक्ति** में सहायता करने वाले सहयोगियों को खोजने को प्राथमिकता दी होगी। लेकिन वास्तविकता एक अलग एजेंडे की ओर इशारा करती है। इजरायल ने **एक आपराधिक गिरोह** का समर्थन किया, जिसे “लोकप्रिय बल” के नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व यासर अबु शबाब कर रहा था। यह समूह **सहायता काफिलों की लूट और गाजा के काले बाजार में भोजन को अत्यधिक कीमतों पर पुनर्विक्रय** करने के लिए जिम्मेदार था। गाजा में और उसके बाहर कई लोग जानते थे कि **यासर अबु शबाब को उनकी अपनी बेदुईन जनजाति ने अस्वीकार कर दिया और निष्कासित कर दिया**, जिसने उसे और उसके गिरोह को गैरकानूनी घोषित किया था।

यह हसबारा कथानक में एक मूलभूत विरोधाभास को उजागर करता है - बंधकों की चिंता करने और भुखमरी को हथियार के रूप में उपयोग करने से इनकार करने का दावा करना - जबकि एक साथ उन आपराधिक सहयोगियों का समर्थन करना जिनका मुख्य उपलब्धि थी **अपने ही लोगों से भोजन चुराना**।

देशद्रोह और सजा

हर राज्य, चाहे वह किसी भी विचारधारा या भूगोल का हो, देशद्रोह को सबसे गंभीर अपराधों में से एक मानता है। युद्ध के समय, अपने लोगों के साथ विश्वासघात घातक परिणाम ला सकता है - न केवल सेनाओं और सरकारों के लिए, बल्कि उन नागरिकों के लिए भी जिनका जीवन उनके समाज की नाजुक एकजुटता पर निर्भर करता है। इस कारण से, **लगभग हर देश का आपराधिक और सैन्य कानून गद्दारों के लिए सबसे कठोर दंड निर्धारित करता है**, जिसमें अक्सर आजीवन कारावास या फांसी शामिल होती है। इतिहास उदाहरणों से भरा पड़ा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप द्वारा नाज़ी सहयोगियों के साथ व्यवहार से लेकर शीत युद्ध के दौरान जासूसों की फांसी तक, सरकारों ने हमेशा कठोर सजा के साथ वफादारी की पवित्रता का बचाव किया है।

यहां तक कि उन राज्यों में जो मृत्युदंड से दूर हो गए हैं, **देशद्रोह अपराधों की श्रेणी में एक विशेष स्थान रखता है** - अक्सर यह उन अंतिम अपराधों में से एक है जो अभी भी मृत्युदंड के लिए योग्य हैं। **संयुक्त राज्य अमेरिका** में, संघीय कानून अभी भी देशद्रोह के लिए फांसी की अनुमति देता है। **भारत, पाकिस्तान, और बांग्लादेश** में, देशद्रोह और संबंधित “राज्य के

खिलाफ युद्ध छेड़ने” जैसे अपराध अभी भी मृत्युदंड योग्य अपराध हैं। यही बात **चीन, उत्तर कोरिया, ईरान, और सऊदी अरब** जैसे देशों पर लागू होती है, जहां राजनीतिक या जासूसी से संबंधित आरोपों के लिए नियमित रूप से मृत्युदंड लागू किया जाता है। यहां तक कि **सिंगापुर और मलेशिया** में, देशद्रोह कानूनी रूप से मृत्युदंड ला सकता है। दुनिया भर की कई सरकारें अभी भी मानती हैं कि अपने देश के साथ विश्वासघात इतना गंभीर अपराध है कि यह अंतिम सजा को उचित ठहरा सकता है।

और फिर भी, जब फिलिस्तीनी सहयोगियों को सजा देते हैं - ऐसे व्यक्तियों को जो भूखी आबादी तक मानवीय सहायता पहुंचने से रोकने के आरोपी हैं - उन्हें एक ऐसे लोगों के रूप में चित्रित नहीं किया जाता जो अपनी रक्षा कर रहे हैं, बल्कि कानूनविहीन भीड़ के रूप में जो बर्बरता से कार्य कर रहे हैं। वही पर्यवेक्षक जो अपने देशों में गद्दार की कठोर सजा का समर्थन करेंगे या स्वीकार करेंगे, **नैतिक आक्रोश** व्यक्त करते हैं जब फिलिस्तीनी अपनी रक्षा के लिए कार्य करते हैं।

मार्शल लॉ और पाखंड

कुछ हसबारा प्रचारक अब कहते हैं कि गाजा में कथित सहयोगियों को निष्पक्ष सुनवाई दी जानी चाहिए थी। यह एक सुविधाजनक बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो युद्ध के बीच में विश्वासघात पर प्रतिक्रिया देने के लिए फिलिस्तीनियों को असभ्य के रूप में चित्रित करने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन यह जानबूझकर जमीन पर वास्तविकता को नजरअंदाज करता है: **गाजा में अब कोई कार्यशील न्यायिक व्यवस्था नहीं है।** इजरायल की विनाशकारी अभियान के बाद, **कोई अदालतें नहीं हैं, कोई जेल की कोठरियां नहीं हैं, और बहुत संभावना है कि कोई जीवित जज या अभियोजक नहीं बचे हैं।** पूरे पड़ोस को समतल कर दिया गया है। मंत्रालय, पुलिस स्टेशन, अदालतें - सब कुछ चला गया है। वे संस्थाएं जो सामान्य रूप से आपराधिक जांच और कानूनी कार्यवाही को संभालती थीं, बमबारी से धूल में मिल गई हैं। ऐसी परिस्थितियों में, अदालत में सुनवाई की मांग न केवल अवास्तविक है - यह कपटपूर्ण है।

यही कारण है कि **मार्शल लॉ का अस्तित्व है:** यह एक कानूनी ढांचा है जो तब काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब नागरिक बुनियादी ढांचा अब कार्यशील नहीं रहता। मार्शल लॉ कोई खामोशी नहीं है - यह वह अंतिम व्यवस्था है जब समाज ढह जाता है। और यहां तक कि मार्शल लॉ, जब इसे ठीक से लागू किया जाता है, **में उचित प्रक्रिया के लिए प्रावधान शामिल होते हैं**, भले ही यह एक सरल, सैन्य रूप में हो। यह शायद टेलीविजन पर प्रसारित अदालत की तरह न दिखे, जिसमें सूट में वकील हों, लेकिन यह अभी भी न्याय के बुनियादी नियमों का पालन करने के लिए है - खासकर जब समय, सुरक्षा, और समुदाय का अस्तित्व दांव पर हो।

अब इसकी तुलना इजरायली व्यवस्था के **खुले पाखंड** से करें। इजरायल ने दशकों से नियमित रूप से **फिलिस्तीनियों के खिलाफ सैन्य कानून** का उपयोग किया है, न कि इसलिए कि उसके पास कार्यशील अदालतें नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि सैन्य कानून **राज्य को अधिक शक्ति और कम सीमाएं देता है।** बच्चों को सैन्य ट्रिब्यूनल में खींचा जाता है। हिरासत में लिए गए लोगों को महीनों तक बिना सुनवाई के रखा जाता है। सबूतों को सार्वजनिक किए बिना सजा सुनाई जाती है। इजरायल का मार्शल लॉ का उपयोग आवश्यकता के बारे में नहीं है - यह वर्चस्व और नियंत्रण के बारे में है।

तो जब आलोचक अचानक गाजा में “उचित प्रक्रिया” के लिए जुनून खोज लेते हैं, तो अपने आप से पूछें: जब इजरायल ने वेस्ट बैंक में नागरिकों पर मार्शल लॉ लागू किया तब यह चिंता कहां थी? जब इजरायल बिना सुनवाई के फिलिस्तीनी घरों को बुलडोजर करता है तब यह कहां है? जब प्रशासनिक हिरासत का उपयोग लोगों को बिना किसी आरोप के अनिश्चितकाल के लिए जेल में डालने के लिए किया जाता है? जब बच्चों से बिना वकील की उपस्थिति में पूछताछ की जाती है?

यह न्याय के बारे में नहीं है। यह **नाटकीय आक्रोश** के बारे में है - कानून और मानवाधिकारों की भाषा का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को बदनाम करने के लिए जो पहले से ही घेराबंदी में हैं।

जानबूझकर छोड़ दिया गया

जो लोग **दुश्मन के साथ सहयोग** करने का चुनाव करते हैं, वे आमतौर पर युद्ध समाप्त होने पर **सुरक्षा या निकासी** की मांग करते हैं। यह जासूसी का एक अलिखित नियम है: जो लोग विश्वासघात करते हैं, उन्हें खरीदा जाना चाहिए - न केवल पैसे से, बल्कि बचाव के वादों के साथ। जो एजेंट शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वे शायद ही कभी वफादारी से

कार्य करते हैं; वे डर, हताशा, या अवसरवाद से कार्य करते हैं। और वे लगभग हमेशा उम्मीद करते हैं कि उनके हैंडलर युद्ध समाप्त होने पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

गाजा में, यह अभी भी अस्पष्ट है कि क्या यासर अबु शबाब और उनके “लोकप्रिय बल” गिरोह को इजरायल की ओर से ऐसी कोई गारंटी दी गई थी। हालांकि, जो तेजी से संभावना प्रतीत होता है, वह यह है कि **इजरायल ने अपने वचन को पूरा नहीं किया** - या कि कोई वास्तविक व्यवस्था कभी थी ही नहीं। जमीनी स्तर से मिली रिपोर्टें बताती हैं कि जब युद्धविराम प्रभावी हुआ, तो ये सहयोगी **खुला छोड़ दिए गए**, बिना निकासी या सुरक्षा के, और उस समाज के क्रोध का सामना करना पड़ा जिसका उन्होंने शोषण किया था।

यह पहली बार नहीं होगा जब कोई शक्तिशाली राज्य अपने **स्थानीय प्रॉक्सी को त्याग देता है** जब उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। यही पैटर्न अफगानिस्तान, इराक, और वियतनाम में दोहराया गया, जहां दुभाषिए, मुखबिर, और विदेशी सेनाओं की सेवा करने वाली मिलिशिया को बाद में **छोड़ दिया गया**, अक्सर उनकी अपनी समुदायों द्वारा गद्दारों के रूप में शिकार किया गया। कब्जा करने वाले के लिए, ऐसे व्यक्ति सुविधा के उपकरण हैं - अभियान के दौरान मूल्यवान, लेकिन जब उद्देश्य बदल जाता है तो खर्च करने योग्य।

डिस्पोजेबल संपत्तियां, उपयोगी मौतें

यदि इजरायल चाहता, तो वह निकासी की व्यवस्था कर सकता था या उन्हें शरण दे सकता था, लेकिन इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि **इन व्यक्तियों का मूल्य जीवित रहने की तुलना में मृत्यु में अधिक था**। उनकी फांसी उपयोगी हो गई - सैन्य रूप से नहीं, बल्कि **कथात्मक रूप से**। सहयोगियों को हमास या स्थानीय मिलिशिया के हाथों में गिरने देना सुनिश्चित करके, इजरायल ने यह सुनिश्चित किया कि ये लोग उस तरह की तेज, सार्वजनिक सजा का सामना करेंगे जिसे बाद में **फिलिस्तीनी क्रूरता के सबूत के रूप में प्रसारित** किया जा सकता था। हसबारा एजेंटों और मीडिया ने इस अवसर को लपक लिया: ग्राफिक चित्र और वीडियो साझा किए गए, नैतिक आक्रोश निर्मित किया गया, और एक सवाल जोर-शोर से पूछा गया - “फिलिस्तीनी समर्थक इसे क्यों नहीं निंदा करते?”। यह केवल परित्याग नहीं था। यह **प्रचारात्मक बलिदान** था।

यह रणनीति एक परिचित तर्क का पालन करती है: फिलिस्तीनियों को तर्कहीन, हिंसक, और स्वाभाविक रूप से “सभ्य” मूल्यों जैसे निष्पक्ष सुनवाई और मानवाधिकारों को बनाए रखने में असमर्थ के रूप में प्रस्तुत करना। यह इजरायल को अधिक नैतिक पक्ष के रूप में पेश करने की अनुमति देता है - भले ही वह सामूहिक सजा, भुखमरी के घरों, और गाजा के बुनियादी ढांचे के व्यवस्थित विनाश में संलग्न हो। इस कथानक में, सहयोगी एक व्यक्ति नहीं है। वह एक **प्रॉप**, एक **प्याद**, और अंत में, एक **मीडिया युद्ध के लिए शहीद** है जिसमें दुश्मन की क्रूरता हमेशा पूर्ण प्रदर्शन पर होनी चाहिए। उसका जीवन खर्च करने योग्य है। उसकी मृत्यु राजनीतिक पूंजी है। इस रणनीति को विशेष रूप से प्रभावी बनाता है कि यह पीड़ित और खलनायक की भूमिकाओं को उलट देता है। देशद्रोह, आंतरिक अराजकता, और हताशा को जन्म देने वाली परिस्थितियों को बनाने के लिए जवाबदेह ठहराए जाने के बजाय, इजरायल विश्वासघात के अपरिहार्य परिणामों को यह साबित करने के लिए इंगित कर सकता है कि फिलिस्तीनी समाज सुधार से परे है।

खुले में मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन

यह केवल अटकलें नहीं हैं। सरकारें लंबे समय से **मनोवैज्ञानिक ऑपरेशनों (psyops)** का उपयोग करती रही हैं ताकि नियंत्रित लीक, चयनात्मक परित्याग, और कथात्मक शोषण के माध्यम से जनता की धारणा को हेरफेर किया जा सके। सीआईए से लेकर मोसाद तक, खुफिया एजेंसियां समझती हैं कि युद्ध अब केवल जमीन पर नहीं लड़ा जाता - यह **दिमाग में**, स्क्रीन पर, और हेडलाइंस के माध्यम से लड़ा जाता है।

सहयोगियों को मरने देना - और यह सुनिश्चित करना कि उनकी मृत्यु दृश्यमान हो - कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है:

- **धमकी:** यह गाजा में दूसरों को सहयोग पर विचार करने का संदेश देता है - आप अकेले हैं।
- **अवैधकरण:** यह इजरायल को फिलिस्तीनी प्रतिरोध को क्रूर और अवैध के रूप में चित्रित करने की अनुमति देता है।
- **विचलन:** यह इजरायली युद्ध अपराधों से ध्यान हटाता है एक विवाद निर्मित करके जिसके खिलाफ फिलिस्तीनियों को अपनी रक्षा करनी पड़ती है।

- **विभाजन:** यह फिलिस्तीनी समाज के भीतर अविश्वास बोता है, यह विश्वास बढ़ाता है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि अपने ही लोगों के बीच में भी।

पश्चिमी मीडिया में चयनात्मक आक्रोश

यदि आप गाजा में युद्ध की मुख्यधारा की अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवरेज का अनुसरण करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि सबसे जरूरी मानवाधिकार चिंता कुछ कथित सहयोगियों की फांसी थी। ये मामले - नाटकीय फुटेज, भारी संपादित हेडलाइंस, और कठोर नैतिकता के साथ प्रसारित - ने पश्चिमी समाचार नेटवर्क पर सेगमेंट्स पर कब्जा कर लिया है, सोशल मीडिया को भर दिया है, और फिलिस्तीनी समाज की तथाकथित “बर्बरता” के बारे में अंतहीन बहसों को बढ़ावा दिया है।

इस बीच, **फिलिस्तीनियों की सामूहिक मृत्यु** - पिछले दो वर्षों में केवल **67,600 से अधिक इजरायली बलों द्वारा मारे गए** - को एक तरह की नौकरशाही तटस्थता के साथ रिपोर्ट किया जाता है। यदि इसका उल्लेख भी किया जाता है, तो यह इजरायली बंधकों, सैन्य अभियानों, या “हमास बुनियादी ढांचे” के बारे में हेडलाइंस के नीचे दबी एक सांख्यिकी के रूप में दिखाई देता है।

यह असमानता केवल संपादकीय लापरवाही नहीं है - यह **कथात्मक इंजीनियरिंग** है।

6, 10, या यहां तक कि 20 सहयोगियों की फांसी दसियों ह हजार सिविल मौतों की तुलना में अधिक हेडलाइंस क्यों उत्पन्न करती है? इसका जवाब इस बात में निहित है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया को कैसे **इजरायली पीड़ा को मानवीय बनाने और फिलिस्तीनी प्रतिरोध को अपराधी बनाने** के लिए कंडीशन किया गया है, जबकि फिलिस्तीनी मृत्यु को या तो संदिग्ध, आकस्मिक, या दुर्भाग्यपूर्ण रूप से “अपरिहार्य” माना जाता है। इजरायली मिसाइल हमले से एक फिलिस्तीनी की मृत्यु को मौसम की घटना की तरह रिपोर्ट किया जाता है - दुखद, लेकिन अव्यक्तिगत। हालांकि, फिलिस्तीनियों द्वारा एक सहयोगी की फांसी **नैतिक रंगमंच** है: यह एक अवसर है कि एंकर, पंडित, और राजनेता पूरे लोगों की मानवता पर सवाल उठाएं।

यह कोई दुर्घटना नहीं है। यह दशकों की **अमानवीकरण**, नस्लवाद, और पश्चिमी मीडिया के वैचारिक, वित्तीय, और राजनीतिक रूप से इजरायली कथाओं के साथ संरेखण का परिणाम है। कवरेज में असंतुलन इस बारे में नहीं है कि क्या समाचार योग्य है; यह इस बारे में है कि क्या प्रभुत्वशाली शक्ति संरचना की सेवा करता है।

अपवाद का सनसनीखेज बनाना, नियम को मिटाना

फांसी परेशान करने वाली हैं, और वे जांच के लायक हैं। लेकिन गाजा में, वे **अपवाद** हैं, नियम नहीं। दूसरी ओर, इजरायली हवाई हमले **नियमित** हैं, जिन्हें अक्सर “सटीक हमलों” के रूप में वर्णित किया जाता है, भले ही वे पूरे पड़ोस को मिटा देते हैं। इन हमलों ने हजारों बच्चों को मार डाला, अस्पतालों को ध्वस्त कर दिया, और एक आबादी को सामूहिक विस्थापन तक भुखमरी में डाल दिया। फिर भी, **राज्य-प्रायोजित औद्योगिक हत्या की क्रूरता** को युद्ध-ग्रस्त सड़क पर एक संदिग्ध गद्दार के जुलूस की तुलना में कम भावनात्मक कवरेज मिलता है।

क्यों? क्योंकि सहयोगी कथानक एक उद्देश्य की पूर्ति करता है: यह पश्चिम के गहरे जड़ जमाए पूर्वाग्रहों की पुष्टि करता है। यह एक सात्वनादायक कहानी सुनाता है जहां **फिलिस्तीनी समस्या हैं**, यहां तक कि उनकी अपनी पीड़ा में भी। जहां हमास - और विस्तार से, सभी फिलिस्तीनी - तर्कहीन, प्रतिशोधी, और कहीं और पीड़ितों को दी जाने वाली सहानुभूति के अयोग्य हैं।

यह पत्रकारिता नहीं है - यह **वैचारिक रखरखाव** है।

उपसंहार

पिछले दो वर्षों में, कहानी को **कब्जा करने वाले की नजर से** बताया गया है, न कि कब्जे में रहने वालों की।

हमने देखा है कि कैसे सहयोगी - बाहरी शक्ति के उपकरण - को मंच के केंद्र में ले जाया गया, जबकि सामूहिक कब्रों में दफन बच्चों को अदृश्य बना दिया गया। हमने “सभ्य” शब्द को व्यवहार के मानक के रूप में नहीं, बल्कि नस्लीय और राजनीतिक

श्रेष्ठता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होते सुना है। हमने न्याय के लिए पुकार को प्रचार के साधनों में विकृत होते देखा है - कमजोरों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उनकी अमानवीकरण को गहरा करने के लिए।

हसबारा कथानक इस उलटफेर पर निर्भर करता है। यह भ्रम पर फलता-फूलता है - इस विश्वास पर कि उपनिवेशितों को हमेशा अपने दर्द, अपने गुस्से, और यहां तक कि अपने अस्तित्व को भी उचित ठहराना चाहिए। जब सहयोगियों को फांसी दी जाती है, तो यह बर्बरता है; जब गाजा पर बमबारी की जाती है, तो यह सुरक्षा है। जब फिलिस्तीनी प्रतिरोध करते हैं, तो यह आतंकवाद है; जब वे चुपचाप मरते हैं, तो यह शांति है। वह नैतिक व्यवस्था जो शक्तिहीनों को जीवित रहने के लिए निंदा करती है और शक्तिशाली को मारने के लिए माफ करती है, वह कोई नैतिक व्यवस्था नहीं है - यह साम्राज्य द्वारा लिखित एक स्क्रिप्ट है, जिसे मीडिया द्वारा निभाया जाता है, और उन लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है जो खंडहरों में अपने स्वयं के प्रतिबिंब को देखने के लिए बहुत सुन्न हो चुके हैं।

सहयोगियों की फांसी एक पतन का लक्षण है - एक ऐसी दुनिया का, जहां कानून और व्यवस्था को बमबारी से धूल में मिला दिया गया है।

वे फिलिस्तीनी बर्बरता का सबूत नहीं हैं, बल्कि **फिलिस्तीन पर थोपी गई बर्बरता** का सबूत हैं।

संदर्भ

- **एसोसिएटेड प्रेस.** “हमास ने गाजा में दो दर्जन से अधिक कथित सहयोगियों को फांसी दी।” **एपी न्यूज**, 14 अक्टूबर 2025।
- **ले मॉन्ड.** “इजरायल का गाजा में सशस्त्र ‘लोकप्रिय बलों’ के लिए गुप्त समर्थन विफल।” **ले मॉन्ड इंटरनेशनल एडिशन**, 10 अक्टूबर 2025।
- **रॉयटर्स.** “गाजा कबीले ने लूट और सहयोग के आरोपों के बीच यासर अबु शबाब को अस्वीकार किया।” **रॉयटर्स**, 11 अक्टूबर 2025।
- **द वीक (यूके).** “‘लोकप्रिय बल’ कौन हैं? गाजा में इजरायल के प्रॉक्सी के पतन के अंदर।” **द वीक**, 12 अक्टूबर 2025।
- **संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय के लिए कार्यालय (OCHA).** **मानवीय प्रभाव स्थिति रिपोर्ट #59: गाजा पट्टी में बुनियादी ढांचे और शासन क्षति मूल्यांकन.** 3 अक्टूबर 2025।
- **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR).** “गाजा की नागरिक संस्थाओं और न्यायपालिका का विनाश।” प्रेस विज्ञप्ति, 25 सितंबर 2025।
- **यू.एस. कोड टाइटल 18 § 2381 - देशद्रोह.** संयुक्त राज्य सरकार प्रकाशन कार्यालय, 2024 तक वर्तमान।
- **बी’त्सेलेम - कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकारों के लिए इजरायली सूचना केंद्र.** सैन्य हिरासत में नाबालिग: वेस्ट बैंक में इजरायली सैन्य अदालतें, 2024 अपडेट।
- **अदमीर कैदी समर्थन और मानवाधिकार संगठन.** प्रशासनिक हिरासत सांख्यिकी और कानूनी संक्षेप, मई 2025।
- **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद.** कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र, जिसमें पूर्वी यरुशलम, और इजरायल पर स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग की रिपोर्ट, A/HRC/59/73, जून 2025।
- **एसोसिएटेड प्रेस.** “गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय: मृतकों की संख्या 67,600 तक पहुंची।” **एपी न्यूज**, 14 अक्टूबर 2025।
- **हारेत्ज़.** “इजरायली सेना ने गाजा की स्थानीय मिलिशिया का उपयोग खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए स्वीकार किया।” **हारेत्ज़ इंग्लिश एडिशन**, 9 अक्टूबर 2025।
- **इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप.** **युद्धविराम के बाद: गाजा में विखंडन और प्रतिशोध**, रिपोर्ट नंबर 248, अक्टूबर 2025।
- **अल जज़ीरा इंग्लिश.** “हमास का कहना है कि उसने फांसी से पहले सहयोगियों को चेतावनी दी थी; इजरायल ने हत्याओं की निंदा की।” **अल जज़ीरा**, 15 अक्टूबर 2025।
- **ह्यूमन राइट्स वॉच.** **इजरायल/फिलिस्तीन: गाजा में सामूहिक सजा समाप्त करें.** 1 अक्टूबर 2025।
- **रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स.** **मीडिया कथानक और युद्ध कवरेज: गाजा 2025**, अक्टूबर 2025।